

(5)

(1)

मध्यप्रदेश शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक 211 / B1 / सीसी / 10 - अडतीस

भोपाल दिनांक 21/8/10

प्रति,

श्री सुरेश एन विजयशर्मा  
अध्यक्ष  
सांस्कृतिक ज्ञान कल्याण परमाणिक न्यास  
भदनापुर, भोपाल (MP)

विषय-मध्यप्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव- पीपुल्स प्राइवेट  
यूनिवर्सिटी भोपाल MP20।

संदर्भ-मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, का पत्र 316 दिनांक 23/6/2010 एवं  
विनियामक आयोग की अनुमति दिनांक 17.6.10

मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायः प्रस्ताव का परीक्षण किया  
गया। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की अनुमति पत्र क्रमांक 316 दिनांक  
23.6.10 के अनुसार राज्य शासन द्वारा निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के अग्रणी संस्था के  
प्रस्ताव पर अशाय-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर जारी करने का निर्णय लिया गया है कि प्रायः की  
नियमों द्वारा मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संभालन) अधिनियम 2007 में  
उल्लंघित तमस्त शर्तों एवं विहित प्रक्रिया का पालन करने की कर्तव्यकारी निर्धारित प्रक्रिया का  
अवधि।

शर्तें निम्नानुसार हैं -

1. यह-
  - (क) मुख्य परिसर स्थापित करना।
  - (ख) धारा 11 के उपबंधों के अनुसार विद्यालय निधि स्थापित करना।
2. यह स्थापित किये जाने वाले मुख्य परिसर के लिए न्यूनतम 20 हेक्टर पर भूमि प्रायः प्रस्ताव  
और उसके स्वामित्व संबंधी कागजात प्रस्तुत करना।
3. का प्रशासकीय प्रयोजन तथा शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने के लिए भवन तथा अनुपनी  
संरचनाओं रूप में न्यूनतम 2500 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र उपलब्ध करायेगा।
4. यह निम्नलिखित प्रभाव का परिचय देना कि-
  - (क) निजी विश्वविद्यालय एकलपक्ष तथा स्वयंसेवक होगा।
  - (ख) निजी विश्वविद्यालय की भूमि तथा भवन का उपयोग कक्षा निजी विश्वविद्यालय  
प्रयोजन हेतु किया जाएगा।

NAAC

- (ग) निजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के लक्ष्य, परचय तथा कक्षाएं प्रारंभ होने के पूर्व प्रत्येक विभाग में या विषय(डिपार्टमेंट) में आवश्यक सहयोगी कर्मचारियों सहित प्रांगण सव्वा में सक्काय सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी ।
- (घ) यह छात्रों को लाभ हेतु विविध प्रकार के निकायों द्वारा अधिकतम मानकों के अनुसार उचित शैक्षणिक तथा स्वस्थ वातावरण को प्रोत्साहित करने हेतु सह-पाठ्यक्रम विद्यालय जैसे संगीत, साहित्य, प्रशस्त, कार्यक्रम तथा पाठ्येतर विद्यालय जैसे खेल, खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा स्कीम, नेशनल क्रेडिट कोर्स आदि को करेगा ।
- (ङ) यह निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम प्रारंभ करेगा
- (च) यह ऐसी अन्य शर्तों को पूरी करेगा तथा ऐसी अन्य जानकारी देगा जैसा कि केंद्रीय विद्यालय निकायों द्वारा समय-समय पर विहित की जाए ।
- (छ) विद्यालय निकाय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त कार्यक्रम सक्काय अधीनस्थान सुविधाओं द्वितीय व्यवहारिता की शर्तों को न्यूनतम मापदण्डों में पूरा करेगा ।
- (ज) यह स्नातक तथा स्नातकोत्तर उपाधि या उपाधिपत्र के मुख्य अध्ययन कार्यक्रम की रचना करेगा जो सुसंगत विनियमों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या संबंधित कानूनी निकायों के मानकों की पूर्ति करेगा ।
- (झ) यह विविध प्रकार के निकायों या मार्गदर्शकों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया तथा जीस के निर्णय को अन्तर्गत करेगा ।
- (ञ) कक्षा नेशनल क्रेडिट और एंजलमेंट एण्ड एक्सेलेंसिटी द्वारा आवश्यक रूप से निर्धारण तथा प्रत्यायोजन किया जाएगा ।
- (ट) निजी विश्वविद्यालय का अध्यापन कर्मचारियों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य उच्च विद्यालय आयोग द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता रखेगा तथा उसको समुचित पारिश्रमिक सटल करेगा ।
- (ठ) निजी विश्वविद्यालय सक्काय व्यक्तियों के लिए चाहे वह किसी भी लिंग का हो खुला रहेगा और जाति, पंथ धर्म वंश के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा तथा निजी विश्वविद्यालय के लिए यह सिद्धिपूर्ण नहीं होगा कि वह धार्मिक विश्वास के आधार पर किसी भी व्यक्ति या निजी विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने या उसमें किसी अन्य पद के धारण करने या उसे निजी विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश दिए जाने या उसके किसी विशेषधिकार का उपयोग या प्रयोग करने का हक्कदार बनाने की दृष्टि से किसी भी प्रकार परीक्षण कर या उस पर कोई परीक्षण होवे ।
- (ड) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संबंधित परिनिधियों तथा अध्यादेशों के अनुषंगाने राज तक प्रवेश तथा कक्षाओं का कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा ।

(ग) विधायक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विवेक रिपोर्ट यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रांतीय निकाय ने उपरोक्त उपबन्धों का पालन कर लिया है तथा उसके प्रस्ताव के अन्तर्गत एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा सकता है, तो वह अनुसूची का संशोधन करने हेतु विधेयक नाम तथा विवरण सहित, जैसे कि अनुसूची में द्वारा निर्दिष्ट विधेयक नाम, एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा।

(द) ऐसा निजी विश्वविद्यालय अनुसूची के संशोधन की तारीख से निर्गमित हुआ समझा जाएगा।

(ए) निजी विश्वविद्यालय अनुसूची में दर्शाए गए ऐसे नाम से एक निर्गमित निकाय होगा जिसका इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए शाश्वत उत्तराधिकार होगा एवं उसकी प्रकृतियाँ तथा शक्ति जो सम्पत्ति अधीन कर सकेगा तथा उसका स्थापित होगा, करार कर सकेगा तथा उस नाम से वाद चला सकेगा तथा उस पर वाद चलाया जा सकेगा।

(ग) ऐसे निजी विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध प्रस्तुत समस्त वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में अधिचमन कुलसचिव द्वारा हस्तक्षरित तथा सत्यापित किये जाएंगे और ऐसे वाद या कार्यवाहियों में समस्त आधिकार कुलसचिव को जारी की जाएगी तथा उस पर लागू हो सकेगी।

5 राज्य सरकार से अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(2) में यथा उपबन्धित आरक्ष-पत्र प्राप्त होने पर यदि कोई प्रांतीय निकाय शर्तों को पूरा करना चाहता है तथा आरक्ष-पत्र में यथा उपबन्धित परिश्रम देता है तो वह बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिन तथा अन्तर्गत) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की प्रथम अनुसूची में तत्स्थानी नये बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट बैंक में पन्द्रह दिन के भीतर शाश्वत निकाय के रूप में पत्र करीब की विचार निधि स्थापित करेगा।

6 अधिनियम की धारा 9(2) के प्रावधान के अनुसार, ऐसा निजी विश्वविद्यालय अनुसूची के संशोधन की तारीख से निर्गमित हुआ समझा जाएगा, के प्रावधान के अनुसार अनुसूची के संशोधन की तारीख से और उसके पश्चात् से विश्वविद्यालय संचालन एवं छात्रों के प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी।

  
(डी०एस० परिहार)  
अवर सचिव  
12 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. 812 / 81 / 10 / सीसी / अखतीस

भोपाल दिनांक 31/3/15

प्रतिलिपि -

1. अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
2. सचिव महामहिम राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मध्यप्रदेश।
3. विशेष सहायक माननीय जी. उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
4. सचिव निदेशक एम सी टी ई एवं अध्यक्ष/सचिव/एम सी आई / डी ई सी एम  
कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली
5. आयुक्त उच्च शिक्षा, सचिवालय, सतपुडा भवन, भोपाल।
6. अध्यक्ष निजी वि०वि०विनियामक आयोग, भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय परिसर, जोलार रोड  
भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अतिरिक्त सचिव उच्च शिक्षा (योजना शाखा) सतपुडा भवन भोपाल की ओर  
सूचना हेतु।
8. सचिव प्रतिष्ठित सचिव उच्च शिक्षा भोपाल रायपुर (सहाय) भोपाल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग